दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 26 मई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 235

महत्वपूर्ण एवं खास

एनडीआरएफ अकादमी में निदेशक पद का होगा सृजन

❍ केंद्रीय कैबिनेट ने इस पद के लिये दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने आज नागपुर स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी में निदेशक के एक पद के सृजन को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में निदेशक पद के सृजन के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एनडीआरएफ अकादमी में निदेशक के पद के सृजन के साथ, संगठन की कमान और नियंत्रण एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी को सौंपा जाएगा, जो तय उद्देश्यों के अनुसार संस्थान का संचालन कर सकता है। अकादमी एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचल बल (एसडीआरएफ), अन्य हितधारकों और दक्षेस व अन्य देशों की आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों के 5000 से अधिक कर्मियों को वार्षिक कौशल आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। भारत और मालदीव के बीच प्राचीन काल से ही जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध बने रहे हैंद्ध भविष्य के लिए भारत की दूरगामी सोच में पड़ोस पहले नीति और ऋसएजीएआर (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन) 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास' के तहत मालदीव का प्रमुख स्थान है। अड्डू शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति और बढ़ेगी और इससे वर्तमान संबंधों और आकांक्षाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। इस समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह के नेतृत्व में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध अप्रत्याशित रूप से नए आयाम और ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह; सबका साथ सबका विकास, की हमारी संवृद्धि और विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकता की नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम भी हैद्ध भारत की राजनयिक उपस्थिति में बढ़ोतरी से भारतीय कम्पनियों को वहां के बाजारों में अपनी पैठ बनाने और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी इससे आत्मनिर्भर भारत के हमारे लक्ष्यों के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि पर भी सीधा असर होगा।

आंध्र प्रदेश में एचपीसीएल के संयंत्र में लगी आग , कोई हताहत नहीं

विशाखापत्तनम (आरएनएस)। शहर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के संयंत्र में आज भीषण आग लग गयी लेकिन वहां उस समय कार्यरत सभी लोग सुरक्षित बताये जा रहे हैं। आग पर तत्काल काबू पा लिया गया और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। ''हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।'' एचपीसीएल के दलों के अलावा पूर्वी नौसैनिक कमान और आंध्र प्रदेश राज्य आपदा मोचन तथा अग्निशमन विभाग की टीमों ने आनन-फानन में मोर्चा संभालकर आग को काबू में कर लिया। एचपीसीएल के पुराने टर्मिनल में क्रूड डिस्टिलेशन इकाई-3 में आग लगी थी। तत्काल आपातकालीन सायरन बज गया जिसके बाद कर्मचारी संयंत्र से बाहर निकले। कुछ कर्मचारियों ने बताया, ''विस्फोट जैसी जोरदार आवाज आई और भयावह आग दिखाई दी। सायरन बजने लगे और हम सब सुरक्षित बाहर आ गये।

यास के उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ने और अगले 12 घंटों में तीव्र होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसारः (शनिवार, 25-5-2021 जारी करने का समय- 1215 बजे, भारतीय समय के अनुसार) पूर्वमध्य तथा निकटवर्ती मध्यपूर्व और उत्तर बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान 'यास' - (ओडिशा- पश्चिम बंगाल तट के लिए चक्रवात की चेतावनी नारंगी संदेश) पूर्वमध्य तथा निकटवर्ती पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान 'यास' पिछले 6 घंटों में लगभग 17 किलो मीटर प्रति घंटे की गति से उत्तरपश्चिम दिशा की ओर बढ़ा और आज 25 मई को सुबह भारतीय समायानुसार 0830 बजे अक्षांश 18.3एउत्तर और देशांतर 88.3एपूर्व के निकट दक्षिण-दक्षिणपूर्व पारादीप (ओडिशा) से 280 किलो मीटर, बालासोर (ओडिशा) से 380 किलो मीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व, दीघा(पश्चिम बंगाल) 370 किलो मीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व और सागर द्वीप समूह (पश्चिम बंगाल) से 370 किलो मीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में पश्चिममध्य तथा निकटवर्ती पूर्वमध्य और उत्तर बंगाल की खाड़ी में केंद्रित हो गया।

अगले 12 घंटों में इसके उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ने और तीव्र होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। यह उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ता रहेगा, तेज होगा और बुधवार 26 मई को सुबह चांदबाली-धामरा बंदरगाह के बहुत नजदीक उत्तर ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के तटों के निकट उत्तरपश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। यह बुधवार 26 मई को दोपहर अति गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में धामरा के उत्तर और दक्षिण बालासोर के बहुत निकट पारादीप और सागर द्वीप के बीच ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों को पार करेगा।

❒ **ओडिशा** : 25 मई को अनेक स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा जगतसिंहपुर, केंद्रापाड़ा,भद्रक,बालासोर जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा; पुरी, खुर्दा, कटक, जाजपुर, मयूरभंज में भारी से बहुत भारी वर्षा और गंजाम, ढेनकनाल, क्योंझर जिलों में भारी वर्षा, 26 मई को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, जगतसिंहपुर, केंद्रापाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, कटक, ढेनकनाल, क्योंझर में कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा, पुरी, खुर्दा, अंगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, 27 मई को उत्तर ओडिशा के भीतरी भागों में भारी वर्षा की चेतावनी।

❒ **पश्चिम बंगाल** : 25 मई को अनेक स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना में बहुत भारी वर्षा तथा हावड़ा, हुगली, कोलकाता और 24 परगना जिलों में भारी वर्षा, 26 मई को मेदिनीपुर के कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा, झारग्राम, बांकुरा, दक्षिण 24 परगना के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा तथा पुरुलिया, नादिया, मुर्शिदाबाद, पूर्व वर्धमान, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, उत्तर 24 परगना, हल्दिया दार्जिलिंग, कलिम्पोंग जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और 27 मई को झारग्राम,पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिम वर्धमान, बीरभूम, मालदा, दार्जिलिंग ,कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा।

❒ **झारखंड** : 25 मई को अनेक स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा, 26 तथा 27 मई को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा।

❒ **बिहार** : 27 मई को अनेक स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, 28 मई को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा।

❒ **असम तथा मेघालय** : 25 और 26 मई को अनेक स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा तथा कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा।

❒ **हवा की चेतावनी** : मध्य बंगाल की खाड़ी के प्रमुख हिस्सों और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में 100-110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा बढ़ कर 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैऔर आज शाम से धीरे-धीरे 125-135 से बढ़कर 140 किमी प्रति घंटे हो जाएगी। उत्तर बंगाल की खाड़ी और उत्तर आंध्र प्रदेश-ओडिशा-पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तटों के पास और उससे दूर हवा 55-65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ कर 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा

कोरोना की करीब डेढ़ महीने बाद दिखी कम रफ्तार

» देश में पिछले 24 घंटे में सबसे कम 1,96,427 नए मामले, 3511 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के दो लाख से कम दैनिक मामले 41 दिनों बाद सामने आए। एक दिन में 1,96,427 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,69,48,874 हो गई। इससे पहले 14 अप्रैल को एक दिन में संक्रमण के 1,84,372 नए मामले सामने आए थे।जबकि इस दौरान 3511 की मौत के बाद देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,07,231 हा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 3,511 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,07,231 हो गई। देश में 21 दिन बाद मौत के इतने कम मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी 25,86,782 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 9.60 प्रतिशत है। देश में कुल 2,40,54,861 लोग अभी तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 89.26 प्रतिशत है। कोविड-19 से मृत्यु दर 1.14 फीसदी है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सिततंबर को 40 लाख से ज्यादा हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्तूबर को 70 लाख, 29 अक्तूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख के पार गए। वहीं, 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार और चार मई को दो करोड़ के पार चले गए।

ब्लैक फंगस से निपटने के लिए नहीं होगी दवा की कमी

» केंद्र सरकार ने लिए कई अहम फैसले

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना महामारी के साथ ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। ऐसे में इस खतरनाक महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार अहम फैसले ले रही है। सरकार इसके उपचार के लिये दवा के उत्पादन बढाने के लिए कई कदम उठाये हैं।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि देश में ब्लैक फंगस दवा के उत्पादन की क्षमता को तीन लाख से बढ़ाकर प्रतिदिन सात लाख कर दिया गया है। ब्लैक फंगस की दवा की सात लाख शीशियों का आयात करने का फैसला किया गया है। 31 मई से पहले तीन लाख शीशीयां आ जाएंगी। जून के पहले और दूसरे हफ्ते में और तीन लाख आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि जून में लगभग 15-16 लाख (एम्फोटेरिसिन बी) शीशियों का उत्पादन होने की उम्मीद है। भारत में आठ लाख शीशियों का उत्पादन होगा, जबकि आयात से हम सात लाख शीशियों की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अभी छह कंपनियां यह दवा बना रही थीं। इनके अलावा पांच और कंपनियों को दवा बनाने की इजाजत दे दी गई है। मौजूदा कंपनियां भी उत्पादन बढ़ाना शुरू कर चुकी हैं। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों ने इस दवा के छह लाख वॉयल्स के आयात का आर्डर भी दे दिया है।

❒ **इन पांच और कंपनियों को मिली इजाजत**

एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, नाटको फार्मा, गुफिक बायो साइंसेस लि., एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स , लायका फार्मास्यूटिकल्स, ये कंपनियां पहले से ही बना रहीं एम्फोटेरिसिन-बी, मायलन, भारत सीरम्स, बीडीआर फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, लाइफ केयर

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में हिंसा के बाद पलायन पर जताई नाराजगी, ममता सरकार से मामले पर मांगा जवाब

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की वजह से राज्य से लोगों के कथित पलायन को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य से लोगों का कथित पलायन रोकने के लिए निर्देश दिए जाएं तथा इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

न्यायमूर्ति विनीत शरण तथा न्यायमूर्ति बीण्आरण् गवई की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ;एनएचआरसीद्ध और राष्ट्रीय महिला आयोग ;एनसीडब्ल्यूद्ध को इस मामले में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। इससे पहलेए याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू ने पश्चिम बंगाल में लोगों की स्थिति का जायजा लिया है। राज्य में चुनाव बाद होने वाली हिंसा के कारण लोगों के पलायन की जांच एसआईटी से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई सात जून को होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा कि पीड़ितों और हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए आवश्यक राहत का पता लगाने के लिए इन आयोगों को प्रतिवादी बनाना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के कारण राज्य में लोगों का सामूहिक पलायन और आंतरिक विस्थापन हुआ है। पुलिस और श्राज्य प्रायोजित गुंडेश् आपस में मिले हुए हैं। यहीं वजह है कि पुलिस मामलों की जांच नहीं कर रही है और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही हैं जो जान का खतरा महसूस कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि इस डर और भय की वजह से लोग विस्थापित या पलायन करने को मजबूर हैं। वे पश्चिम बंगाल के भीतर और बाहर आश्रय गृहों या शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। याचिका में एक लाख से अधिक लोग विस्थापन का दावा किया गया है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 21.89 करोड़ से अधिक खुराक की गई प्रदान

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है। कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है। रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50 प्रतिशत खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था। भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके की 21.89 करोड़ से अधिक खुराक (21,89,69,250) मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत (अपव्यय सहित) 19,93,39,750 खुराक (आज सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) है।

बस्तर में नक्सलियों पर वार से बहने लगी विकास की बयार, सुरक्षा-बलों के कैंपों ने नक्सलियों को पीछे धकेल बस्तर में बहाल किया लोकतंत्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। नक्सलियों के सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले बस्तर में सुरक्षा बलों की मोर्चाबंदी ने जहाँ उनकी कमर तोड़ दी है वहीं अब विकास की बयार भी बहने लगी है।

नक्सलियों के लाल किले को भेदने के साथ ही नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास पर काम किया जा रहा है। यहां अब सड़क,स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं बहाल होने लगी हैं।

छत्तीसगढ के बस्तर में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा-बलों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए जाने की जो रणनीति अपनाई गई है, उसने अब नक्सलवादियों को अब एक छोटे से दायरे में समेट कर रखा दिया है। इनमें से ज्यादातर कैंप ऐसे दुर्गम इलाकों में स्थापित किए गए हैं, जहां नक्सलवादियों के खौफ के कारण विकास नहीं पहुंच पा रहा था। अब इन क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है, यातायात सुगम हो रहा है, शासन की योजनाएं प्रभावी तरीके से ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं, अंदरुनी इलाकों का परिदृश्य भी अब बदल रहा है।

बस्तर में नक्सलवादियों को उन्हीं की शैली में जवाब देने के लिए सुरक्षा-बलों ने भी घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों में अपने कैंप स्थापित करने का निर्णय लिया। इन कैंपों की स्थापना इस तरह सोची-समझी रणनीति के साथ की जा रही है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हर कैंप एक-दूसरे की मदद कर सके। इन कैंपों के स्थापित होने से इन इलाकों में नक्सलवादियों की निर्बाध आवाजाही पर रोक लगी है। सुरक्षा-बलों की ताकत में कई गुना अधिक इजाफा होने से, नक्सलवादियों को पीछे हटना पड़ रहा है। सुरक्षा-बलों की निगरानी में सड़कों, पुल-पुलियों, संचार संबंधी अधोसंरचनाओं का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में भी शासन की योजनाएं तेजी से पहुंच रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों की समस्याओं की सूचनाएं अधिक त्वरित गति से प्रशासन तक पहुंच रही हैं, जिसके कारण उनका समाधान भी तेजी से किया जा रहा है। गांवों में चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास तेजी से हो रहा है। कुपोषण, मलेरिया और मौसमी बीमारियों के खिलाफ अभियान को मजबूत मिल रही है, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सक रही है। इन बीमारियों की वजह से सैकड़ों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं, इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सर्वाधिक रही है। बस्तर में लोकतांत्रिक प्रणाली को उत्तरोत्तर मजबूती मिलने से बौखलाए नक्सली इन कैंपों का विरोध कर रहे हैं। वे कभी इन कैंपों पर घात लगाकर हमले करते हैं, तो कभी ग्रामीणों के बीच गलतफहमियां निर्मित कर उन्हें सुरक्षा-बलों के खिलाफ बरगलाते हैं। बस्तर की सबसे बड़ी समस्या ग्रामीणों और प्रशासन के बीच संवाद की कमी रही है। कैंपों की स्थापना से संवाद के अनेक नये रास्ते खुल रहे हैं, जिससे विकास की प्रक्रिया में अब ग्रामीणजन भी भागीदार बन रहे हैं।

बस्तर के वनवासियों को वनों से होने वाली आय में इजाफा तो हो ही रहा है, उनकी खेती-किसानी भी मजबूत हो रही है। छत्तीसगढ़ के दूसरे क्षेत्रों के किसानों की तरह वे भी अब अच्छी उपज लेकर अच्छी कीमत प्राप्त कर रहे हैं। वनअधिकार पट्टा जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने के साथ-साथ वे तालाब निर्माण, डबरी निर्माण, खाद-बीज आदि संबंधी सहायता भी प्राप्त कर रहे हैं। कैंपों की स्थापना के बाद अधोसंरचनाओं के विकास से वनोपजों और कृषि उपजों की खरीदी-बिक्री में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है, अब ग्रामीण जन शासन द्वारा तय किए गए समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच पा रहे हैं। बीमार अथवा आपदा-ग्रस्त ग्रामीणों को तेजी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं।